NEXT IAS

दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

श्वेत क्रांति 2.0: भारत के डेयरी उद्योग के लिए एक नया अध्याय

www.nextias.com

श्वेत क्रांति 2.0: भारत के डेयरी उद्योग के लिए एक नया अध्याय

सन्दर्भ

- आज़ादी के पश्चात् से भारत के डेयरी उद्योग में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है, जो दूध की कमी वाले देश से विश्व के सबसे बड़े दूध उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में विकसित हुआ है। हालाँकि, अपनी उपलब्धियों के बावजूद, उद्योग को ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके लिए श्वेत क्रांति 2.0 की आवश्यकता है।

भारत में श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, के बारे में

- इसे 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) द्वारा डॉ. वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में लॉन्च किया गया था, जिन्हें प्रायः 'श्वेत क्रांति का जनक' कहा जाता है।
- इसने देशी गायों को उच्च उपज देने वाली विदेशी नस्लों के साथ क्रॉसब्रीडिंग, पशु पोषण में सुधार और दूध प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने जैसी पहलों के माध्यम से दूध उत्पादन को काफी बढ़ावा दिया।
- फलस्वरूप, भारत का दूध उत्पादन 1950-51 में 17 मिलियन टन से बढ़कर 2022-23 में 230.58 मिलियन टन हो गया।
- बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी (BAHS) 2023 के अनुसार, शीर्ष पांच दूध उत्पादक राज्य यूपी (15.72%), राजस्थान (14.44%), मध्य प्रदेश (8.73%), गुजरात (7.49%) और आंध्र प्रदेश (6.70%) हैं, जो देश के कुल दूध उत्पादन में 53.08% का योगदान करते हैं। BAHS के अनुसार, कुल दूध उत्पादन का लगभग 31.94% देशी भैंसों से आता है, उसके बाद संकर नस्ल के मवेशियों से 29.81% आता है।
    - 12.87% हिस्सा गैर-विशिष्ट भैंसों का है, 10.73% देशी मवेशियों का है, और 9.51% गैर-विशिष्ट मवेशियों का है। बकरी के दूध का हिस्सा 3.30% है, और विदेशी गायों का हिस्सा 1.86% है।

श्वेत क्रांति 2.0 की चुनौतियां और आवश्यकता

- **उत्पादकता:** भारत में प्रति गाय औसत दूध उत्पादन अपेक्षाकृत कम है। उदाहरण के लिए, विदेशी या संकर गायें प्रतिदिन केवल 8.52 लीटर दूध देती हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में उनकी समकक्ष गायें प्रतिदिन लगभग 30 लीटर दूध देती हैं।
    - जबकि कुल दूध उत्पादन 2018-19 में 187.75 मिलियन टन से बढ़कर 2022-23 में 230.58 मिलियन टन हो गया, इस अवधि के दौरान उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 6.47% से घटकर 3.83% हो गई।
    - उत्पादकता के इस अंतर के कारण मांग-आपूर्ति में असंतुलन बढ़ रहा है और दूध की कीमतें बढ़ रही हैं।
- **मांग में उछाल:** जनसंख्या वृद्धि, प्रोटीन स्रोत के रूप में दूध की सार्वभौमिक अपील और पोषण पर बढ़ते ध्यान ने मांग को बढ़ा दिया है। हालाँकि, उत्पादन गति बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है।
- **लागत दबाव:** बढ़ती फ़ीड लागत दूध उत्पादन की कुल लागत में योगदान करती है। दूध की कीमतें व्यापक मुद्रास्फीति से आगे निकल रही हैं, अगर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो खपत कम होने का जोखिम है।

    - दूध के लिए स्थिर और लाभकारी कीमतों की कमी डेयरी किसानों की आय को प्रभावित करती है, जिससे उनके लिए अपने कार्यों की योजना बनाना और निवेश करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **पशु स्वास्थ्य और प्रजनन सेवा प्रावधान:** रोग, उचित प्रजनन प्रथाओं की कमी और अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं जैसे मुद्दे पशुधन के समग्र स्वास्थ्य तथा गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।
- **प्रौद्योगिकी अपनाना:** किसानों के बीच जागरूकता, शिक्षा और प्रशिक्षण की कमी कृत्रिम गर्भाधान, कुशल खिला विधियों और रोग प्रबंधन जैसी उन्नत प्रथाओं के कार्यान्वयन में बाधा डालती है।
- **गुणवत्ता मानक:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पाद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं, गुणवत्ता नियंत्रण उपायों तथा स्वच्छता प्रथाओं के पालन में निवेश की आवश्यकता होती है।

श्वेत क्रांति 2.0 में प्रवेश

- श्वेत क्रांति 2.0 का विचार सहकारी समितियों के आस-पास घूमता है, जो पांच दशक पहले ऑपरेशन फ्लड का आधार भी थीं। यह कई प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है:
- **महिला किसानों को सशक्त बनाना:** डेयरी फार्मिंग में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, कार्यक्रम का उद्देश्य उन्हें अधिक सशक्त बनाना है। प्रशिक्षण, ऋण तक पहुंच और बाजार संपर्क प्रदान करके, यह क्षेत्र में उनकी भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास करता है।
- **दूध संग्रह को बढ़ावा देना:** प्राथमिक लक्ष्य अगले पांच वर्षों में देश भर में दूध संग्रह को 50% तक बढ़ाना है।
    - इसका अर्थ है 2028-29 तक दैनिक दूध की खरीद 660 लाख किलोग्राम से बढ़ाकर 1,007 लाख किलोग्राम करना।
- **डेयरी सहकारी समितियों के विस्तार के अवसर:** 2021 में इसके निर्माण के बाद से, सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों, विशेष रूप से डेयरी सहकारी समितियों के नेटवर्क का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया है सरकार इसे 2028-29 तक बढ़ाकर 1,007 लाख किलोग्राम/दिन करना चाहती है।
    - राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) ने अगले पांच वर्षों में लगभग 56,000 नई बहुउद्देशीय डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करने और अधिक उन्नत दूध खरीद तथा परीक्षण बुनियादी ढांचे प्रदान करके 46,000 वर्तमान ग्राम स्तरीय DCSs को मजबूत करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। अधिकांश नए DCSs उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे।

भारत में डेयरी सहकारिताओं पर आंकड़े

- भारत में डेयरी उद्योग के नियामक, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के अधिकारियों के अनुसार, देश के लगभग 70% जिलों में डेयरी सहकारी समितियाँ संचालित होती हैं।
- लगभग 1.7 लाख डेयरी सहकारी समितियाँ (DCS) हैं, जो लगभग 2 लाख गाँवों (देश के कुल गाँवों की संख्या का 30%) और 22% उत्पादक परिवारों को कवर करती हैं।
- ये सहकारी समितियाँ देश के दूध उत्पादन का लगभग 10% और विपणन योग्य अधिशेष का 16% खरीदती हैं।

राज्यवार डेयरी सहकारी समितियां

- गुजरात, केरल और सिक्किम राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 70% से अधिक गाँव डेयरी सहकारी समितियों द्वारा कवर किए गए हैं।
- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, कवरेज केवल 10-20% है।
- पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के छोटे राज्यों में 10% से भी कम गाँव कवर किए गए हैं।

- **वित्त पोषण:** श्वेत क्रांति 2.0 के लिए अधिकांश वित्त पोषण राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) 2.0 के माध्यम से आएगा, जो पशुपालन और डेयरी विभाग के तहत एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है।
  - केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने श्वेत क्रांति 2.0 के लिए पूर्ण बजटीय सहायता का आश्वासन दिया, इसकी प्राथमिकता स्थिति पर बल दिया।
  - इसके अतिरिक्त, गुजरात में सफलतापूर्वक संचालित 'सहकारी समितियों के बीच सहयोग' पहल का देश भर में विस्तार किया जाएगा। यह सहकारी सहयोग को बढ़ावा देते हुए RuPay-किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से डेयरी किसानों को ब्याज मुक्त नकद ऋण प्रदान करता है।
- **प्रौद्योगिकी अपनाना:** भ्रूण स्थानांतरण और सेक्स-सॉर्टेड वीर्य जैसी आधुनिक तकनीकें उत्पादकता में सुधार की कुंजी हैं। ये नवाचार प्रजनन परिणामों, आनुवंशिक स्टॉक और मादा बछड़ों की संभावना को बढ़ाते हैं, जिससे अंततः दूध की पैदावार बढ़ती है।
- **डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना:** कार्यक्रम दूध संग्रह, प्रसंस्करण और वितरण के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर बल देता है। इसमें जिला सहकारी समितियों, बहुउद्देश्यीय समितियों और दूध मार्गों से जुड़ी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) की स्थापना और वृद्धि शामिल है।
- **डेयरी निर्यात को बढ़ावा देना:** श्वेत क्रांति 2.0 वैश्विक बाजारों में भारत के डेयरी क्षेत्र की क्षमता को पहचानती है। उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार करके, इस पहल का उद्देश्य डेयरी निर्यात को बढ़ावा देना है, जिससे किसानों और अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ होगा।

श्वेत क्रांति 2.0 के प्रमुख घटक

- **रुपे किसान क्रेडिट कार्ड:** डेयरी किसानों के लिए देश भर में रुपे किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत से ऋण और वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुँच की सुविधा मिलती है। ये कार्ड किसानों को अपने वित्त का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने में सक्षम बनाते हैं।
- **डेयरी सहकारी समितियों में माइक्रो-एटीएम:** डेयरी सहकारी समितियों में माइक्रो-एटीएम स्थापित करने से बैंकिंग सेवाएँ सीधे किसानों के दरवाज़े तक पहुँचती हैं। यह कदम वित्तीय समावेशन और सुविधा को बढ़ाता है।
- **PACS का कम्प्यूटरीकरण:** प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के कम्प्यूटरीकरण के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएँ जारी की गई हैं। यह डिजिटल परिवर्तन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है और ऋण और सहकारी गतिविधियों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करता है।

संबंधित सरकारी पहल

- **राष्ट्रीय गोकुल मिशन:** इसका उद्देश्य देशी मवेशियों की नस्लों का संरक्षण और विकास करना तथा देशी मवेशियों की उत्पादकता और आनुवंशिक सुधार को बढ़ाना है।
- **राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले दूध के उत्पादन के साथ-साथ राज्य सहकारी डेयरी संघ के माध्यम से दूध और दूध उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण तथा विपणन के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण या सुदृढ़ीकरण करना है।
- **डेयरी उद्यमिता विकास योजना:** इसे डेयरी उद्योग में स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
    - यह छोटे से मध्यम स्तर के डेयरी उद्यम स्थापित करने के लिए व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम:** यह 100% मवेशियों, भैंसों, भेड़, बकरी और सूअर की जनसँख्या का टीकाकरण करके खुरपका और मुँहपका रोग और ब्रुसेलोसिस के नियंत्रण के लिए शुरू की गई एक प्रमुख योजना है।
- **राष्ट्रीय पशुधन मिशन:** इसे कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, और इसका उद्देश्य डेयरी खेती सहित पशुधन क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करना है।
    - यह पशुधन की उत्पादकता बढ़ाने, उनके स्वास्थ्य में सुधार करने और चारा और चारा संसाधनों के लिए सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है।

निष्कर्ष

- श्वेत क्रांति 2.0 महिलाओं को सशक्त बनाने, दूध उत्पादन में सुधार लाने और भारत के डेयरी क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सहयोग, नवाचार और सतत प्रथाओं को बढ़ावा देकर, इस पहल का उद्देश्य देश के डेयरी उद्योग के लिए सफलता का एक नया अध्याय लिखना है।

Source: BL

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न. 'श्वेत क्रांति 2.0' के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारतीय डेयरी उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।

■■■■